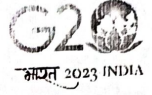




कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग  
रामनगर (नैनीताल)



(संशोधित)

dfo\_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक /  
सेवा में,

दिनांक,

// 2024

वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में संशोधित आख्या।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1849/12-1 दिनांक 26.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी 3 बिन्दुओं पर सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित की जा रही है:-

1. **For what propvision lease was sanctioned?:-** उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की शा०दे०सं० 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975(संलग्न-1) से श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं० 08 एवं 09 की 2700 वर्गफी० वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374/14-2-578/74 दिनांक 26.06.1978(संलग्न-2) के माध्यम से सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि:-

“ यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से “ नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट” प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।”

इस प्रकार लीजधारक को प्रश्नगत लीज भूमि पर कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।

2. **Is there any violation of lease deed?** लीजधारक द्वारा प्रश्नगत लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, कृषि सेवा केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है।

साथ ही लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है की भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को खुलवाया गया था। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति बनाई गयी, जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते हुए इनके पुनर्वास की अनुशंसा की गई थी। तब भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा में भी इन इंजीनियरों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री की सहमति से प्रभावित इंजीनियरों को पेट्रो प्रोडक्ट की पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देने आदि के लिए साक्षात्कार के द्वारा आवंटन दिया गया। (छायाप्रति संलग्न-3)



3. **Lease originally was granted till 2005. Why it has not been renewed after 2005?** इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु प्रथम आवेदन वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008(संलग्न-4) द्वारा किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा पुनः पत्राचार वर्ष 2013(संलग्न-5) में किया गया, जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनीकरण प्रस्ताव गठित कर उलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 को प्रस्ताव आनलाईन माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् समय-समय पर विभिन्न स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्राचार अतिथि तक गतिमान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है की शा0सं0 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 की बिन्दु सं0 3 में स्पष्ट किया गया है की:-

“ कृपया विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेज दें एवं पट्टेदार को निदेश दें कि वे 32 रू0 विधीक्षण शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट कन्वेयेन्सर, उ0प्र0 विधान भवन लखनऊ के पास भेज दें:-

“065 अन्य सामान्य सेवायें-क-अन्य प्रशासन -। - सेवायें तथा सेवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस” “

1. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अवगत कराना है की इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पट्टाविलेख तैयार नहीं किया गया है।
2. उक्त लीज वर्ष 2005 तक स्वीकृत थी, जिसके नवीनीकरण हेतु लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम पत्राचार किया गया। वर्तमान तक लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में FCA 1980 के प्रवाधानों के तहत उक्त लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
3. उक्त लीज हेतु लीज रेन्ट वर्ष 2005 तक जमा किया गया है। प्रश्नगत लीज के नवीनीकरण हेतु लीज रेन्ट का आगणन जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 03/5-स्टाम्प/मूल्यांकन-2022-23(संशोधित दर सूची) दिनांक 16.02.2023(संलग्न-6) के द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है:-

भूमि का मूल्य 1मी <sup>0</sup> के लिए वर्तमान बाजार दर	= रू0 47750.00 / 1मी <sup>0</sup>
के अनुसार	≈ रू0 47,75,00,000.00 / है0
प्रश्नगत लीज नवीनीकरण में प्रस्तावित 0.0250	= 0.0250 X रू0 47,75,00,000.00 / है0
है0 भूमि का मूल्य	= रू0 1,19,37,500.00 / -
उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या	= जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार
1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021	दर X लीज अवधि / 90
के प्रस्तर 3.1.4 के अनुसार प्रीमियम	= रू0 1,19,37,500.00 X 30/90
	= रू0 39,79,167.00 / -
उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या	= प्रीमियम का 5%
1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021	= रू0 198,958.00 / -
के प्रस्तर 3.1.4 के अनुसार वार्षिक लीज रेन्ट	
उपरोक्तानुसार दिनांक 04.07.2005 से आतिथि	= 19 वर्ष X रू0 198,958.00 / -
तक	= रू0 37,80,202.00 / -
19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट	
कुल धनराशि	= प्रीमियम + 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट
	= रू0 39,79,167 / - + रू0 37,80,202 / -
	= रू0 77,59,369.00

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत लीज नवीनीकरण हेतु कुल धनराशि रू0 77,59,369.00 (सतहत्तर लाख  
उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर रूपये मात्र/-) लीज धारक से अपेक्षित है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिगन्थ नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(दिगन्थ नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर



प्रतिलिपि शास. सं 1963/14=2=78/74 दिनांक 3=7=75 प्रेषक, मन्त्रि  
उपप्र. शासन, लखनऊ सेवा, साण्यपाल, प० वृ० उ० प्र० नैनेताल ।

=====

विषय :- श्री हरीश चन्द्र धारिह्याल की कृषि सेवा केन्द्र स्थापना की  
जिला नैनेताल में वन भूमि बिया जाना ।

=====

उपर्युक्त विषय पर आपसे पत्र सं 2673/5=2 (र) दिनांक 3 मार्च  
1975 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल  
महोदय ने श्री हरीश चन्द्र धारिह्याल की कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural  
Implements Workshop) के स्थापना की सम्बन्ध में रातो रात मीटर मार्ग के किनारे  
2700 वर्ग फीट (प्लॉट नं० 8=1425 वर्ग फीट एवं प्लॉट नं० 9=1275 वर्ग फीट)  
भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति  
प्रदान की है :-

1. पट्टेदार उक्त भूमि का 7,500 रु० प्रीमियम एवं 375 रु० वाणिज्यिक करिया  
देगा ।
2. पट्टे की अवधि 30 वर्षों की होगी ।
3. भूमि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है केवल उसी प्रयोजन के लिये  
उपयोग में लाई जायगी । पट्टेदार की पट्टे पर स्वीकृत भूमि को  
आवश्यकता पड़ने पर वह बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही वन भूमि की  
वापस हो जायगी ।
4. पट्टेदार उक्त भूमि को किसी भी भी किसी भी रूप में हस्तान्तरित  
न कर सकेगा ।
5. यदि एक वर्ष के भीतर पट्टेदार द्वारा उक्त केन्द्र पूर्ण रूप से स्थापित  
नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही शासन  
द्वारा वापस ले ली जायगी ।
6. यदि संक्षिप्त अवधि में कृषि सेवा केन्द्र स्थापना हेतु दो गह  
अनुज्ञा दी जायगी तो पट्टेदार भी उसी समय से रद्द माना  
जायेगा ।
7. पट्टे की अवधि की समाप्ति पर अध्यागत शर्तों के उल्लंघन के पक्षवत्  
पट्टेदार रद्द किये जाने पर उक्त वन भूमि बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही  
शासन की वापस हो जायगी एवं पट्टेदार की दो माह का समय दिया  
जायेगा जिसके भीतर वे अपना समस्त सामान एवं निम्नलिखित कार्य  
हस्त में अथवा उक्त समय के बाद जो भी सामान प्रगत भूमि में रहेगा





जायगा वह साक्षर को संपत्ति ही जायगी जिसके लिये पट्टेदार किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

2. प्राप्ति धानाशा आय . व्ययक के प्राप्ति शीर्षक " 113. वन " के मूल उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा को जाय ।

3. कृपया विलेख का आलेख्य प्रामन के अनुमतिनाशर् भीत हैं स्वं पट्टेदार को निदेशा दें कि वे 32 लो विधोक्षाणा शुल्क के सम में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत टैजरो में जमा कराके टैजरो चालान गवर्नमेन्ट. कन्वेन्सर , उ०प्र० विधान सभान लखानऊ के पास भीज दें :-

" 065 अन्य सामान्य सेवाएँ - अन्य प्रामन - सेवाएँ तथा सेवा शुल्क निजो निजायो के लिये काम करने के तास्ते सरकारी कर्मगारियो द्वारा प्राप्त जेस "

4. यह आदेशा वित्त विभाग को पत्रमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके असासकीय सं० ई - 7 = 1431/दस - 75 दिनांक 27-6-75 द्वारा प्रदत्त है ।

प्रतिलिपि सूचनाशर् प्रेषित ।

- 1. महालेखाकर, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2. वित्त (व्यय नियंत्रणा) अनुभाग . 7

आजा से,  
६० एन० पो० त्रिपाठी  
सचिव ।

कार्यालय अति० मुख्य सचिवपाल, कु० उ०प्र० नैनीताल ।

सं० ए. 320/5=2 रा. (स. दिनांक नैनीताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि प्रमाणोय वनाधि कारो रामनगर को उनके पत्र सं० 2500/5=4 दिनांक 7=2=1975 के संदर्भा में सूचनाशर् तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । शान्तिनादेशा के पैरा 3 पर शीर्षक कार्यवाही करें ।

अग्रोपिठ

एवम/के  
प्रधान सचिव

(द्वितीय प्रसाद लेशी )  
अति० मुख्य सचिवपाल, कु० उ०प्र०  
नैनीताल ।

सं. 168/31/75 दिनांक 27-6-75

व.प्र.क. 4/15



प्रतिलिपि सासनादेश संख्या 6371/44-2-578/74, लखनऊ, दिनांक, जून 26, 1978 वन अनुभाग -2, प्रेषक श्री रनओपो त्रिपाठी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा में अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनोताल।

विषय:- श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ जिला नैनोताल में वन भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6378/5-2 रा0, दिनांक जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि श्री धिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनोताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नौ आलेखन सर्वेफिकेट" प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 4963/44-2-578/84, दिनांक जुलाई 3, 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर खोदून भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

362  
5-4 (हरीश चन्द्र धिल्डियाल)  
15/7 "A"

आवेदन संख्या  
अनुभाग-2  
15/7/78

कार्यालय अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उत्तर-प्रदेश, नैनोताल।  
पत्र संख्या 17738 / 52(R) दिनांक : नैनोताल, जुलाई 78  
प्रतिलिपि प्रभागोय वनाधिकारी रागनगर को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6378/5-2 (रा0) 11 दिनांक 16-6-78 के क्रम में सूचना एवं उक्त शासनादेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उ०प्र०, नैनोताल।  
10/7

वि/13

विषय:- पेट्रोल तथा डिजेल पम्प खोलने की अनुमति चाहिए हेतु।

प्रसंग:- उक्त कार्यालय की पत्र सं. 3843/5-4 दि. 14-4-78

जिला कृषि अधिकारी को आवेदन के आधार पर प्रकृत-वां जमीन-आदि कार्यवाही की जा सकती है।

पत्र संख्या

चन्द्र  
दिनांक  
जुलाई  
म में  
दिनांक  
12  
गोदावरी  
सेक्टर  
आउट  
दिनांक  
652  
024  
सूचना प  
नैनोताल



(S)

(7)

✓

10/87  
N. B. S. S. S.

(9) Pages

REVISED DRAFT

SCHEME

FOR

REHABILITATION

OF

BLACK APRO SERVICE MEMBER

The scheme was developed in 1987 in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987.

The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987.

The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987. The scheme was developed in response to the need for a rehabilitation scheme for Black APRO service members who were discharged from the Army in 1987.



①

UNSTARRED QUESTION NO. 1238  
TO BE ANSWERED ON THE 11<sup>TH</sup> MARCH, 1982  
DECLINE OF AGRICULTURE SERVICE CENTRES

1238. SHRI B. P. SINGH  
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a large number of agro-service centres in the country are in a difficult position and that more than 500 such centres have been closed down, while many are on the verge of bankruptcy; and
- (b) if so, details thereon along the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI N.V. SWAMINATHAN)

(a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Budni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihar, Haryana, J & K, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, 75% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre, Hissar in 1978 revealed that 67.5% agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981 508 out of 3206 centres (i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that many of these centres are on the verge of bankruptcy.

(b) Details: State-wise position of break-up of 508 centres reported to have been closed is given in annexure.

Reasons for the failure :

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure of closing down of some of these centres was low work turn-over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor-owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below :-

- 1) These agro-service centres were given priority allotment of tractors both indigenous and imported.
- 11) The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to these agro-service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

②  
③  
④  
⑤  
⑥  
⑦  
⑧  
⑨  
⑩  
⑪  
⑫  
⑬  
⑭  
⑮  
⑯  
⑰  
⑱  
⑲  
⑳  
㉑  
㉒  
㉓  
㉔  
㉕  
㉖  
㉗  
㉘  
㉙  
㉚  
㉛  
㉜  
㉝  
㉞  
㉟  
㊱  
㊲  
㊳  
㊴  
㊵  
㊶  
㊷  
㊸  
㊹  
㊺

Contd. P.O.



iii) At various stages seminars and conferences were held to discuss the performance of these centres. It was advised to diversify their business on a wide basis as per the local demands and not confine themselves to repairing tractors alone.

iv) The Ministry of Finance advised the RBI to advise the nationalised banks to recharge the payment of instalments of bank loans taken by them wherever necessary.

v) On transfer of the scheme to the States, the States were directed to honour the commitments on transfer and to extend such other necessary help as required for running them on viable basis.

vi) Minister of State for Agriculture addressed the Ministers concerned to take such steps as would be required for strengthening these centres, including expenditure on the claims of these agro-service entrepreneurs and subsidy.

vii) Minister (A. R. CS) once again addressed the Ministers of the States to take action to disburse the interest charges of these entrepreneurs urgently, to route the distribution of agricultural inputs in the areas where these centres were functioning through them to help them in getting customizing services in the various schemes implemented by the State Government and their various programmes including programme of soil conservation and command area development. Simultaneously he addressed the Union Finance Minister of instruct the Commercial Banks to waive interest charges on loans advanced to these centres and to facilitate the payment of principle amount. Union Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers was also addressed by him to consider the case of these centres for allotment of a general licence for import and petro-based lubricants.

Note:- AT THE SUPREME COURT : The Agriculture Minister was asked in the Parliament, but not in the Supreme Court to say that the Government may not submit a report. This means that our case may be posted for argument. The latest counter by SBI in Maharashtra still remains a formidable one against us. Sri Nariman has advised us to file such counters even in previous writs. We are asked for Petitioner-wise/ writ-wise/ State-wise. So please send your latest full information.

\*\*\*



## INDEX

Page Number

1.	Name of the Scheme	:	1
2.	Objective of the Scheme	:	1
3.	Eligibility Criteria	:	1
4.	Components of the Scheme	:	
4.1	Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to non viable Agro Service Centres which can not be Rehabilitated.	:	2
4.2	Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.	:	3
4.3	Other assistance to be extended to identified sick agro service centres	:	5
5.	Implementation procedure	:	7



- 1. Name of the Scheme : Rehabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).
- 2. Objective of the Scheme : The Scheme aims at rehabilitation/revival of the identified sick Agro Service Centres set up under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme, which was operated through Agro Industries Corporations at the State Level during the period 1971 to 1979 and later transferred to State sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3. Eligibility Criteria 3.1: The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.

3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.

3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselves.

3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assets will not be considered eligible for any assistance under the scheme.

3.5 Agro-Entrepreneurs who have been defaulters in the past will not be eligible for assistance under the Scheme.

4. Components of the Scheme : Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.

4.1 to be taken 4.1.1 Bank will consider each case on merits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

of non-  
viable Agro Service  
Centres which  
are to be rehabilitated



4.2 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agric Service Centres which can be rehabilitated.

4.2.1 Penal interest and fund interest

If penal rates of interest or charges have been charged such charges should be waived from the accounting year of the unit in which it started incurring cash losses continuously. After this is done, the unpaid interest on term loans and cash credit during this period should be segregated from the total liability and funded. The interest may be charged on funded interest and repayment of such funded interest shall be payable in 3 years from the date of commencement of implementation of the rehabilitation programme.

4.2.2 Unadjusted interest dues

Unadjusted interest dues such as interest charged between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms as 4.2.1 above.

4.2.3 Term loans

The rate of interest on term loans may be reduced, where considered necessary, by not more than three percent, the reduced rate, in no case being less than the rate of interest charged under Integrated Rural Development Programme (IRDP).

4.2.4 Principal dues

After the unadjusted interest portion of the cash credit account is segregated as in 4.2.1 and 4.2.2 above, the interest representing principal dues may be



treated as irregular to the extent it exceeds drawing power. This amount may be funded as Working Capital Term Loan (WCTL) with a repayment schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded item at 10 percent per annum.

4.2.5 Cash Losses

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rehabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the nursing programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financier. But if both are involved in the rehabilitation package, the financial institution concerned should finance such cash losses. Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

4.2.6 Working Capital

Need-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of Rs. 25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per annum.

4.2.7 Contingency loan assistance

For meeting escalations in capital expenditure to be incurred under the rehabilitation programme, banks/financial institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial assistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of contingency loan assistance. Interest on this contingency assistance may be charged at the concessional rate allowed for working capital assistance.

4.2.8 Funds for start-up expenses and working capital

There may be a need to provide the unit with funds for start-up expenses (including payment of pressing creditors' margin).



money for working capital in the form of long-term loans. Where a financial institution is not involved, banks may provide the loan for start-up expenses, while margin money assistance should be provided by State Government where it is operating a margin money scheme. The term loan from banks will carry the same rates as the existing term loans.

4.2.9 Guarantee fee

The guarantee fee payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in respect of sick agro-service centres units should be borne by the Banks/financial institutions during the period of rehabilitation programme.

4.3 Other assistance to be extended to sick agro service centres.

4.3.1 Accommodations

State Governments will consider requirements of agro-entrepreneurs on case to case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a measure has been recommended by District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the sick agro service centre concerned.

4.3.2 Agriculture Inputs Distribution

State Governments and State Agro-Industries Corporations will accord priority to the identified sick agro service centres in matters of giving agencies for input distribution, if such measure has been recommended by the District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the agro service centre concerned. States may consider adopting the Maharashtra pattern in this regard. States may also designate AECs as approved outlets for items in which cooperative do not deal in.

contd., 5/-



7

5. Pending claims of interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agro entrepreneurs in accordance with the provisions of the agro service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in pursuance to the decision of National Development Council.

Implementation procedure.

5.1

The State AICs will be responsible for identification of eligible agro service centres as per the eligibility criterial as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications alongwith rehabilitation proposal for consideration to the concerned State Agro Industries Corporation within 90 days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation will scrutinise the applications received, within a period of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee(DLAC).

5.2

Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Committee constituted as under

- (i) Distt. Collector -Chairman.
- (ii) One representative of Lead Bank. -Member
- (iii) One representative of Creditor Bank. -Member
- (iv) Representative of the Managing Director of State Agro Industries Corporation. -Member-Secretary.

The proposals for rehabilitation considered eligible will be recommended by the DLAC to the concerned bank for further action. Proposals



for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DLAC and the dues of the Bank/Financial Institution shall be recovered in such instalments as may be decided by the Bank/Financial Institution on merits of each case.

The DLAC will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

- i) Secretary (Agri.) : Chairman
- ii) One Representative : Member of Lending Bank
- iii) One representative : Member of Reserve Bank of India.
- iv) One representative : Member of NABARD
- v) One representative : Member of small Industries Service Institute
- vi) Two representatives : Member of agro-entrepreneurs.
- vii) Managing Director of State Agro-Industries Corporation. Secretary

The representative of the agro-entrepreneurs will be selected in a meeting of agro-entrepreneurs, financed under the Centrally Sponsored Scheme of Agro Service Centres, held by the State Agro Industries Corporation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.



: - 7 - :

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4

5.4 A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks, State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district, divisional, regional, zonal and also at head office to sanction the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the prescribed guidelines/Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.





# AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.  
 RANESHET ROAD, RAMNAGAR (JAMNAL) ☎ 35949 RES 35573 OFF 35484

Order No. \_\_\_\_\_

Date 21.02.1988

सेवा से

उभागीय इन्सपेक्टर  
 रामनगर वन प्वाण रामनगर

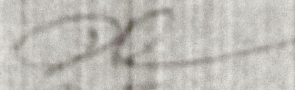
विषय -

एकट सख्या 84 9 के लीज मशीनीकरण करने के सम्बन्ध में ।

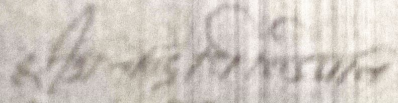
महोदय

विशेषतः इस प्रकार है कि यहाँ का एकट सख्या 84 9 का लीज मशीनीकरण होना है। अतः आप लीज मशीनीकरण करने की अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

अनुरोधित

दि 21/02/88  
 एच. सुभाषिण  
  
 उ. व.  
 अ. सुभाषिण

भवदीय

  
 (हरिहर चन्द्र फिलिमल)  
 एच. सुभाषिण एण्ड विलियम  
 स्टेशन ऑफिस  
 रानेशेट रोड रामनगर  
 (नेनेतास)








**कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर नैनीताल**

दिनांक 16 फरवरी 2023

पत्रांक 03/5-स्टाम्प/मूल्यांकन-1-2022-23(संशोधित दर सूची)

केंद्रीय मूल्यांकन समिति की रास्तुति के पश्चात शासन के पत्र संख्या 615/2023/XXVII(9)/स्टाम्प 80/2019 दिनांक 15 फरवरी 2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद नैनीताल से संबंधित केंद्रीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदित मूल्यांकन सूची दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी दर सूची को संशोधित किया जाता है जो दिनांक 16 फरवरी 2023 से प्रभावी होगी।

  
(धीराज गर्गल)  
जिलाधिकारी  
नैनीताल



जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की सर्किल दरें											
क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)								
			सूचि भूगि की दर (प्रति हेक्टेयर लाख रु० में)	असूचि भूगि की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)		शहुरंगितली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)		गैर वाणिज्यिक निर्माण दर (१० प्रति वर्गमीटर में)		
				0 से 200 मीटर तक	0 से 50 मीटर तक		50 मीटर से अधिक 200 मीटर तक	दुकान रेस्टोरेन्ट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी टिनशेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A	रामनगर-रानीखेत मुख्य मोटर मार्ग पैठपडाव से मोहान तक (बाया डिकुली)									
		1	मोहल्ला रानीखेत रोड (वार्ड नं० 20)	980	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
	A (I)	1	लखनपुर (वार्ड नं० 04)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
		2	पैठपडाव (वार्ड नं० 20)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
		3	टेडा रोड (वार्ड नं० 03)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
	A (II)	1	दुर्गापुरी (वार्ड नं० 02)	980	12000	10500	24000	41700	37200	12000	7000
		2	डिकुली	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		3	लदुवाचौड	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		4	मोहान	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		5	लदुवारी	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
		6	अमरपुर	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
2	B	रामनगर-काशीपुर मुख्य मोटर मार्ग काशीपुर रोड से भवानी गंज तक									
		1	काशीपुर रोड (वार्ड नं० 13)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		2	जसपुरीया लाइन (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		3	भवानी गंज (वार्ड नं० 17)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
3	C	रामनगर नगर पालिका क्षेत्र / वार्ड कसेरा लाईन से ऊटपडाव तक बाया रानीखेत रोड									
		1	कसेरा लाइन (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		2	ज्वाला लाइन (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		3	नन्दा लाइन (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		4	बजाजा लाइन (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
		5	कोसी रोड (वार्ड नं० 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000

6  
ADM